Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

कक्षा-9वीं राजस्थान बोर्ड 2027

ARJUN BATCH

लोकतांत्रिक राजनीति

संस्थाओं का कामकाज

PARLIAMENT
LEGISLATURE
JUDICIARY
EXECUTIVE
PEOPLE

Rajasthan

Constitution
Democracy
Institutions
Citizens
Governance
India

CHAPTER 04 || PART - 04

22 सितंबर 2026 || 05:00 PM

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

आज क्या पढ़ेंगे ?



Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

निर्वाचन → जनता के द्वारा → चुना

हुआ → प्रतिनिधि

या फिर प्रति के द्वारा चुना

मनोनित → किसी व्यक्ति / राष्ट्रपति के द्वारा

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

1. राज्यों की परिषद (राज्यसभा)

(i) ☛ उच्च सदन

(ii) ☛ राज्यों की परिषद → विधानसभा के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित

(iii) ☛ अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित

(iv) ☛ राज्यों से संबंधित मामलों में राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

2. लोकसभा

लोकप्रिय

(i) ☛ निचला सदन | निम्न सदन

(ii) ☛ जनता का सदन

(iii) ☛ जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित

(iv) ☛ जनता की ओर से वास्तविक शक्ति का प्रयोग करती है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

3. भारत के राष्ट्रपति

- भारत के राष्ट्रपति संसद का एक अंग हैं, यद्यपि वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते।
- संसद द्वारा बनाए गए सभी कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही लागू होते हैं।

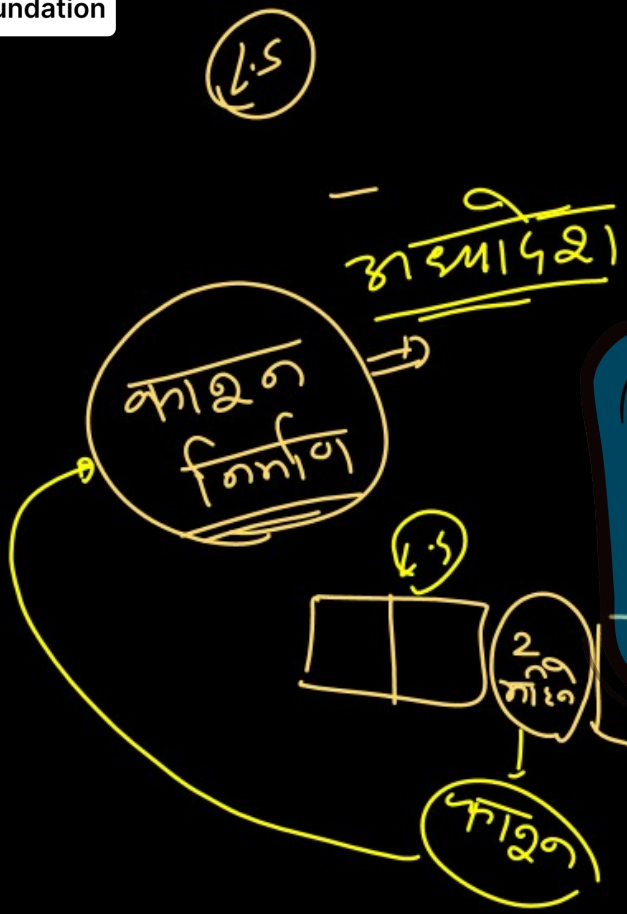



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

लोकसभा	राज्यसभा
543 सदस्य	233 + 12 सदस्य
जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित	विधायकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित
प्रत्येक 5 वर्ष बाद भंग	स्थायी सदन





Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

लोकसभा, राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली

- कानून पारित करना
- वित्तीय मामले
- मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण

mg

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

कानून पारित करना

1. संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा का मत प्रभावी

- साधारण कानूनों के लिए लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की स्वीकृति आवश्यक।
- दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक का आयोजन, जिसमें दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चर्चा और मतदान।
- लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक। इसलिए ऐसी बैठकों में सामान्यतः लोकसभा का निर्णय प्रभावी।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

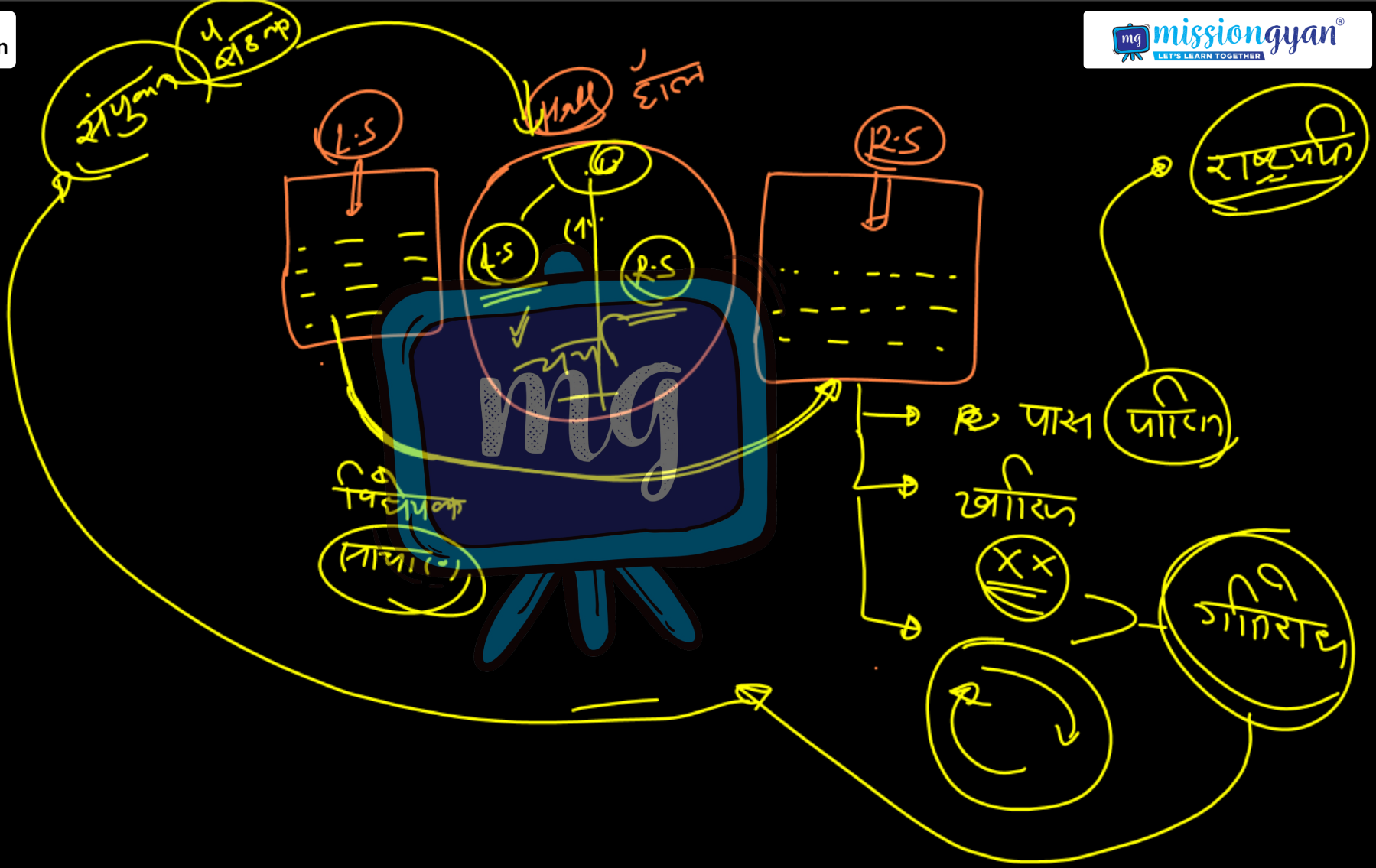

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

वित्तीय मामले

2. वित्तीय मामलों में लोकसभा को अधिक अधिकार

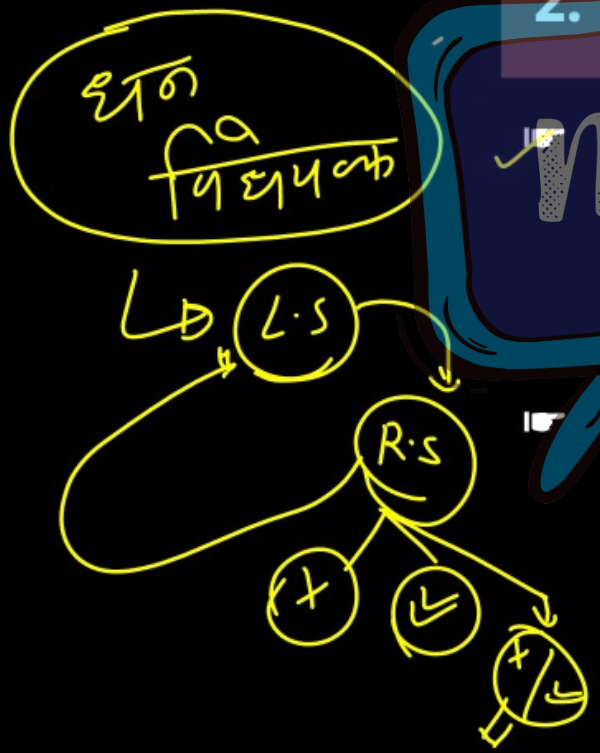

- लोकसभा द्वारा सरकार के बजट या धन से संबंधित किसी कानून को स्वीकृति मिलने के बाद राज्यसभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती।
- राज्यसभा द्वारा केवल 14 दिनों की देरी या परिवर्तनों का सुझाव संभव, लेकिन इन सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार लोकसभा के पास।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण

3. मंत्रिपरिषद पर लोकसभा का नियंत्रण

- प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा के बहुमत सदस्यों का समर्थन आवश्यक।
- लोकसभा द्वारा 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों का त्यागपत्र आवश्यक।
- राज्यसभा के पास मंत्रिपरिषद को हटाने की शक्ति नहीं।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER



राजनीतिक कार्यपालिका

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

कार्यपालिका

राजनीतिक कार्यपालिका



स्थायी कार्यपालिका



प्रतिदिन के निर्णय लेने वाले पदाधिकारी, लेकिन जनता की ओर से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग नहीं।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

राजनीतिक कार्यपालिका

- एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा निर्वाचित।
- जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व और उसके प्रति उत्तरदायी।
- निर्वाचित प्रतिनिधि होने के कारण नीतिगत निर्णयों पर अंतिम अधिकार।
- सरकार बदलने पर पद से हटना।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

स्थायी कार्यपालिका अथवा सिविल सेवाएँ

- दीर्घकालीन आधार पर नियुक्ति, जिन्हें सिविल सेवक भी कहा जाता है।
- संबंधित क्षेत्रों का विशेषज्ञ ज्ञान एवं शिक्षा।
- दैनिक प्रशासन में राजनीतिक कार्यपालिका की सहायता।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

- सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कुशल क्रियान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका।
- सरकार बदलने के बाद भी पद पर बने रहना।

